नवनियुक्त डीईओ आशा दहिया पूरी बारात के साथ कार्यालय पहुंची

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) बीते करीब दस माह से डीईओ (ज़िला शिक्षा अधिकारी)के खाली पड़े पद पर नियुक्त हुई आशा दहिया ने 18 अक्टूबर को कार्यभार सम्भाल लिया। डिप्टी डीईओ रोहतक से पदोन्नत होकर यहां का कार्यभार संभालने का सौदा करीब चार माह पूर्व ही हो चुका था। इससे सम्बन्धित लेन-देन भी हो चुका था। परन्तु इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश, जिसके अनुसार अनुसूचित जाति का कोटा पूरा करना था, के चलते आशा दहिया का काम अटका रह गया था।

खैर, जो भी हो राज्य के शिक्षामंत्री कंवर पाल गूजर अपने सौदे पर ईमानदारी से कायम रहे और सुप्रीम कोर्ट की अड़चना दूर होते ही आशा दहिया को यह ज़िला सौंप दिया जबकि उनके पास और भी बड़ी-बड़ी आर्कषक ऑफर थीं। हालांकि उनको यह लीज केवल सात-आठ महीने के लिए ही मिली है, अप्रैल में तो वो सेवानिवृत्त होने वाली है। यानी जो खेल करना हैं उन्हे इन्हीं सात-आठ महीनों में करना होगा। शिक्षा विभाग के भरोसेमंद सूत्र बताते हैं कि फ़रीदाबाद में डीईओ लगने का रेट पांच से दस लाख तक कुछ भी हो सकता है। इसी तरह अन्य ज़िलों में लूट कमाई की संभावनाओं को देखते हुए अलग-अलग रेट चलते हैं। मंत्री की ओर से सौदेबाज़ी का यह धंधा सुखबीर कौशिक नामक एक बाबू को दिया हुआ है। तबादलों के अलावा और भी अनेकों प्रकार के कामों के लिये भी लेन-देन का काम यही कौशिक करता है। मंत्री के मुंह लगे होने के चलते यह डीओ स्तर तक के अधिकारियों से ऐसे बात करता है जैसे कि वे उसके मातहत हों।

लूट कमाई करने वालों के लिये यह पांच-दस लाख कोई मायने नहीं रखते क्योंकि यहां पर लूट कमाई का धंधा काफ़ी तगड़ा चलता है। डीओ दफ्तर में बैठे बाबूओं की कमाई तो लगभग हर सीट पर हो ही जाती है परन्तु प्राइवेट स्कूलों को डील करने वाली सीट का तो कोई मुकाबला ही नहीं है।

नियुक्ति से प्रफुल्लित आशा दहिया जब चार्ज लेने यहां पहुंची तो उनके साथ करीब 40 लोग थे। आधे से अधिक तो रोहतक से ही साथ आये थे, शेष यहां से शामिल हो गये। अपने साथ आने वाली इस पूरी बारात की सूचना आशा दहिया ने पहले से ही आपने दफ्तर में इस हिदायत के साथ दे दी थी कि इन सबका जलपान तथा लंच का प्रबन्ध किया जाय। लंच के लिये सारे बारात को सेक्टर 16 स्थित ऊं स्वीट्स नामक रेस्तरां में ले जाया गया। यह बताने की जरूरत नहीं है कि सारा खर्चा दफ्तर के उन बाबूओं ने उठाया जिनकी दुकानदारी अब बुलेट ट्रेन की गति से चलने लगेगी। ऐसे में स्कूलों व शिक्षा की हालत क्या होगी बखूबी समझा जा सकता है।

शिक्षा के नाम पर एक और नौटंकी...

पेज एक का शेष

लम्बी-लम्बी छोड़ने में माहिर जुमलेबाज खट्टर इन स्कूलों में रॉकेट साइंस से लेकर रोबोटेक तक न जाने क्या-क्या पढ़ाने की बातें करते हैं। फिलहाल इन स्कूलों को हरियाणा शिक्षा बोर्ड से हटा कर सीबीएसई से जोड़ा जा रहा है। यदि सीबीएसई के साथ जोड़ने से ही शिक्षा की समस्या हल हो जाती है तो हरियरणा बोर्ड क्यों पाल रखा है, इसे भंग करके सीबीएसई से ही सभी स्कूलों को क्यों नहीं जोड़ दिया जाता?

'पीएम श्री' के नाम से खुलने वाले प्रत्येक स्कूल को दो-दो करोड़ रुपये भी दिये जायेंगे। जिससे स्कूल में आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति की जा सके। दरअसल इस तरह से पैसे बांटना अपने आप में ही एक फ्रॉड है। स्कूलों को इस तरह से बांटा गया पैसा शिक्षा बजट में किसी बड़ी सेंधमारी से कम नहीं होता। इस तरह से बांटा गया पैसा अधिकारियों, राजनेताओं व ठेकेदारों के बीच बंट जाता है। इस तरह बांटे गये पैसे से स्कूलों में बनी अनेकों इमारतें उद्घाटन से पहले ही कंडम हो चुकी होती है। उनको गिराने पर होने वाला खर्चा अलग से होता है। कुल मिलाकर शिक्षा विभाग को हरामखोरी व रिश्वतखोरी से मुक्त करने की बजाय खट्टर सरकार को सारा ध्यान नाटकबाज़ी के द्वारा जनता को बहकाने पर रहता है। अभी तक खोले गये तथाकथित मॉडल सांस्कृतिक स्कूलों की दुर्दशा भी देखने लायक है। इन स्कूलों में फीसें तो अच्छी-खासी लगा दी गई हैं लेकिन पढाने वाले शिक्षक व अन्य सम्बन्धित साजो-समान का नितांत अभाव है।

सांसों में ज़हर घोलती प्रदूषण की सरकारी दुकान

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) यूं तो धूल और धुंए से वायू-प्रदूषण हर समय ही बना रहता है, परन्तु अक्टूबर का महीना शुरू होते ही यह प्रदूषण भयंकर रूप लेने लगता है। मौसम में आनेवाले परिवर्तन यानी कि तापमान गिरने तथा वायु गति स्थिर होने के चलते धूल और धुएं के गुबार इधर-उधर जाने के बजाय शहर के पर ही स्थिर हो जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप पूरा शहर तब तक गैस चेम्बर बन कर रह जाता है जब तक कि बारिश एवं वायु गतिशील न हो जाय।

यह सब कोई यकायक हो जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। बीते अनेक वर्षों से यह सिलसिला चला आ रहा है। इससे निपटने के नाम पर सरकारों ने प्रदूषण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसी कमाई की दुकाने खोल रखी हैं। प्रदूषण नियंत्रण ने इनका योगदान केवल चालान करने व पैसे वसूलने तक ही सीमित रहता है। अक्टूबर महीना शुरू होते ही ग्रेप(ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) नाम का नाटक शुरू कर दिया जाता है। इस दौरान डीजल जनरेटर चलाने, भवन निर्माण करने तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुंए पर रोक लगा दी जाती है। इसके साथ-साथ सड़कों से उड़ने वाली धूल को रोकने के लिये पानी छिड़काव की बात की जाती है। इसके अलावा पराली जलाने वाले किसानों पर भी कार्रवाई करने का दावा किया जाता है।

इस तमाम ड्रामेबाज़ी के बावजूद वायु प्रदूषण दिन-ब-दिन बढ़ता ही जाता है। क्योंकि ड्रामेबाजी तो ड्रामेबाजी ही होती है उससे कोई समस्या हल नहीं होती। जब बिजली नहीं मिलेगी तो जेनरेटर चलेंगे ही, भवन निर्माण का काम कोई रोकता नहीं है। फैक्ट्रियों का धुंआ भी ज्यों का त्यों निकलता है। इनको रोकने वाले इसके एवज में अच्छी-खासी लूट-कमाई कर लेते हैं। इसके चलते शहरवासी श्वांस रोग तथा अन्य कई बीमारियों के शिकार होने लगते हैं।

सड़कों से उड़ने वाली धूल को रोकने के लिये पानी छिड़काव के नाम पर मोटे बिल तो जरूर बनते रहते हैं परन्तु छिड़काव कहीं नज़र आता नहीं। नज़र आना सम्भव भी नहीं क्योंकि इतने लम्बे-चौड़े शहर में और वह भी टूटी सड़कों व उनके किनारे पड़ी मिट्टी को गिला करने के लिये सैंकड़ों जल छिड़काव वाहनों की जरूरत है, जो कि सम्भव नहीं दिखता। दूसरी ड्रामेबाजी के तौर पर दो-चार जगह, तथाकथित एन्टी स्मोक गनों द्वारा वायूमंडल में पानी की बौछारें की जाती हैं। यह सब ऊंट के मुंह में जीरे के समान होता है। सड़कों पर झाड़ू लगाने से उड़नेवाली धूल को रोकने के लिये करोड़ों रुपये की विशेष मशीने तो ले ली गई हैं लेकिन उनकी कोई कार्रवाई नज़र नहीं आती। नज़र आ भी नहीं सकती क्योंकि यहां की सड़कें उन मशीनों के लायक बनी ही नहीं है।

असल काम जो करने वाला है और जो आसानी से किया भी जा सकता है, उसे करने में शासन-प्रशासन की कोई रुचि नहीं है। प्रशासन को सैंकड़ों मील 'जलती पराली' का धुंआ तो नज़र आता है परन्तु अपनी नाक के नीचे जलते कूड़े-कबाड़े के ढेर नज़र नहीं आते। कबाड़े में जलने वाली रबर व प्लास्टिक की दुर्गन्ध अधिकारियों व राजनेताओं को कतई महसूस नहीं होती।

सड़कों पर लगने वाले जाम से बढ़ते प्रदूषण का समाधान करने की कोई समझ प्रशासन में नजर नहीं आती। प्रदूषण विभाग की ओर से शहर के कई स्थानों पर घड़ीनुमा यंत्र लगा कर शहरवासियों को यह जरूर बताया जाता है कि वायु का ज़हरीलापन कितनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। समझ नहीं आता कि यह सूचना देकर सरकार अपने नागरिकों से क्या चाहती है? प्रदूषण को रोकने के लिये जनसाधारण के पास न तो कोई अधिकार है और न ही कोई साधन।

यदि नागरिकों ने ही सब कुछ करना है तो इस सरकार नामक बोझ को वे क्यों ढो रहे हैं? इसी सवाल को लेकर लोग सड़कों पर उतरने की बजाय मंदिरों में भजन कीर्तन करते हुए परमात्मा की शरण में रहना ज्यादा पसंद करते हैं।

प्रदूषण से लड़ते वकील ऋषिपाल

सेक्टर 11 निवासी वकील ऋषिपाल शर्मा एक जागरूक नागरिक का फर्ज निभाते हुए प्रदूषण के विरुद्ध जम कर लड़ रहे हैं। यद्यपि उनके पास सरकार की ओर से दिया गया कोई कानूनी अधिकार तो नहीं है, फिर भी वे अपने सेक्टर में जगह-जगह कूड़े के ढेरों में लगी आग की वीडियो बना बना कर उन अधिकारियों व राज नेताओं के पास भेज रहे हैं जिनके पास इन्हें रोकने के अधिकार हैं।

बीते सप्ताह ऋषिपाल ने इस सम्बन्ध में बाकायदा एक लिखित शिकायत नगर निगमायुक्त मोना एश्रीनिवास को भी भेजी है। विदित है कि ऋषिपाल द्वारा कूड़े के जलते जो ढेर अपने वीडियो में दिखाये हैं वे सेक्टर 11 की पुलिस चौकी, राज्य के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा तथा विधायक नरेन्द्र गुप्ता के कार्यालय के आस-पास ही है। इतना ही नहीं ऋषिपाल उन बड़ी कोठी वालों से भी कूड़ा न जलाने का अनुरोध करते हैं जो इस तरह के ढेर जलवाते हैं। इसी तरह का अनुरोध आरडब्लूए के प्रधान विकास चौधरी भी करते नज़र आये हैं। दरअसल कोठी निवासियों को भी कूड़े के ढेर तभी जलाने पड़ते हैं जब नगर निगम के निकम्मे एवं भ्रष्ट अधिकारी इन्हें नहीं उठवाते।

प्रदूषण के विरुद्ध इसी तरह की जंग सेक्टर 55 निवासी गुरमीत सिंह देओल भी लड़ते नज़र आ रहे हैं। वे अपनी वीडियो के द्वारा अन्य स्थानों के अलावा सेक्टर 12 में कूड़े के जलते ढेर लगातार दिखाते आ रहे हैं। कूड़ा जलने का यह स्थान सेक्टर 15ए के फायर स्टेशन के लगभग सामने वहां स्थित है जहां 'हूडा' के दो एक्सईएन व अन्य कर्मचारी अपना दफ्तर चलाते है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।